

प्रेपक,

आलोक कुमार वर्मा,  
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,  
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,  
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : २

देहरादून : दिनांक : २७ जून, २००६

विषय: तेखला, उत्तरकाशी में न्याय विभाग के आवासीय परिसर में कंटीली तार लगाने हेतु वित्तीय वर्ष २००६-०७ में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या ८९५/UHC/Admn.B/Const./2005, दिनांक ५ अप्रैल, २००६ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेखला, उत्तरकाशी में न्याय विभाग के आवासीय परिसर में कंटीली तार लगाने हेतु ₹ १,१४,०००/- आगणन के विरुद्ध ₹ १०००००० द्वारा संस्तुत ₹ १,०६,०००/- (रुपये एक लाख छः हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये १,०६,०००/- (रुपये एक लाख छः हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
- (4) एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय ।
- (5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (6) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की गणि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (7) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।
- (8) जी०पी०डब्ल्यू फार्म ९ की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर १० प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

- (9) किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय ।
- (10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तदविपयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक “2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजनेतर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00-25-लघु निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-356/XXVI(5)/2006, दिनांक 17 जून, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)  
अपर सचिव ।

#### संख्या-3-दो(1)/XXXVI(1)/2006-तददिनांक ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
  2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
  3. वरिष्ठ फोषाधिकारी, उत्तरकाशी ।
  4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
  5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी, उत्तरकाशी ।
  6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
  7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( वीरेन्द्र पाल सिंह )  
अनुसचिव ।